eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed (Refereed) International Journal
Volume 04, Issue 06, June 2025

ईरान–इस्राइल टकराव : मध्य पूर्व में शांति या युद्ध की दस्तक

डॉ0 अरविन्द कुमार शुक्ल[1]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्ना0 महाविद्यालय, बिंदकी फ़तेहपुर उ0प्र0

Received: 29 June 2025 Accepted & Reviewed: 29 June 2025, Published: 30 June 2025

Abstract

ईरान और इस्राइल के मध्य टकराव ने मध्य पूर्व की राजनीतिक स्थिरता, क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक कूटनीति को गहरे रूप से प्रभावित किया है। यह टकराव केवल दो राष्ट्रों के बीच वैचारिक विरोध नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक, धार्मिक, और सामरिक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है।

यह शोध पत्र इस टकराव के ऐतिहासिक, वैचारिक, कूटनीतिक तथा भू–राजनीतिक पहलुओं का विश्लेषण करता है और यह विवेचना करता है कि यह संघर्ष मध्य पूर्व में शांति की संभावना को किस हद तक प्रभावित करता है या संभावित युद्ध की भूमिका तैयार कर रहा है। अमेरिका, रूस, चीन जैसी बाहरी शक्तियों की भूमिका तथा अरब देशों की स्थिति को भी इस अध्ययन में समाहित किया गया है।

अंततः, यह शोध इस निष्कर्ष तक पहुँचता है कि शांति की संभावनाएं अभी भी जीवित हैं, परंतु वे कई जटिल शर्तों और नीतिगत संतुलनों पर आधारित हैं।

मुख्य शब्द – ईरान, इस्राइल, मध्य पूर्व, क्षेत्रीय संघर्ष, भू–राजनीति, परमाणु कार्यक्रम, हिज़्बुल्लाह, अमेरिका, शांति प्रक्रिया, युद्ध की आशंका

Introduction

मध्य पूर्व एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ इतिहास, धर्म, भू–राजनीति और रणनीतिक हित एक–दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में अनेक टकरावों ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया है, लेकिन ईरान और इस्राइल के बीच का तनाव न केवल क्षेत्रीय अस्थिरता का स्रोत रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है।

इस शोध पत्र का उद्देश्य ईरान–इस्राइल टकराव की जड़ों की पहचान करना, उसके ऐतिहासिक व वैचारिक पक्षों का विश्लेषण करना, और यह समझना है कि यह टकराव मध्य पूर्व को शांति की ओर ले जाएगा या किसी बड़े युद्ध की आहट दे रहा है। इसमें बाहरी शक्तियों की भूमिका, सामरिक नीतियाँ, धर्म–संप्रदाय के प्रभाव और ऊर्जा संसाधनों की भू–राजनीति को भी समाहित किया गया है।

परिकल्पना (Hypothesis)– ईरान और इस्राइल के बीच वैचारिक एवं सामरिक टकराव केवल द्विपक्षीय संघर्ष नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक बहुपक्षीय संघर्ष है।

यह टकराव यदि अनियंत्रित रहा, तो क्षेत्रीय युद्ध में परिवर्तित हो सकता है, जिसमें बाहरी शक्तियाँ भी संलग्न होंगी। कूटनीतिक प्रयास, क्षेत्रीय गठबंधनों, और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से इस टकराव को नियंत्रित किया जा सकता है।

ऊर्जा और आर्थिक सहयोग की संभावनाएं इस टकराव को अवसर में बदल सकती हैं यदि नेतृत्व स्तर पर साहसिक निर्णय लिए जाएं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed (Refereed) International Journal
Volume 04, Issue 06, June 2025

शोध प्राविधि (Research Methodology)–

तथ्यात्मक विश्लेषण (Factual Analysis)– अंतरराष्ट्रीय संगठनों (UN, IAEA), रक्षा विश्लेषण संस्थानों और समाचार स्रोतों से संकलित तथ्य।
ऐतिहासिक पद्धति (Historical Method)– 1948 से 2024 तक के ईरान–इस्राइल संबंधों का कालक्रमिक अध्ययन।
तुलनात्मक दृष्टिकोण (Comparative Approach)– अन्य क्षेत्रीय संघर्षों (भारत–पाकिस्तान, कोरिया, यूक्रेन–रूस) से तुलना।
वर्णनात्मक विश्लेषण (Descriptive Analysis)– घटनाओं, समझौतों, और कूटनीतिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण।
साहित्यिक समीक्षा (Literature Review)– विद्वानों, रक्षा विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषकों के कार्यों की समीक्षा।

ईरान–इस्राइल संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य–

प्रारंभिक सहयोग (1948–1979)– इस्राइल की स्थापना (1948) के बाद, ईरान उस समय के कुछ मुस्लिम देशों में से था जिसने इस्राइल को अस्वीकार नहीं किया। पहलवी शासन के दौरान (शाह मोहम्मद रजा पहलवी), ईरान और इस्राइल के बीच कूटनीतिक संबंध थे, जिनमें व्यापार, तेल और खुफिया सहयोग शामिल था। इस्राइल के लिए यह संबंध सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, विशेषकर अरब विरोधी संधियों में ईरान की भूमिका को लेकर।

इस्लामी क्रांति और संबंधों में परिवर्तन (1979 के बाद)– 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद, अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में नया शासन आया, जिसने इस्राइल को शैतान का प्रतीक घोषित किया। तब से दोनों देशों के संबंध शत्रुतापूर्ण हो गए। ईरान ने फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन किया और हमास तथा हिज़्बुल्लाह जैसे संगठनों को सहयोग देना शुरू किया, जिसे इस्राइल ने अपने लिए सीधा खतरा माना।

1990 के बाद और परमाणु विवाद– 1990 के दशक में, जब ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाया, तब इस्राइल की चिंताएँ बढ़ गईं। इस्राइल को आशंका रही कि ईरान का परमाणु हथियारों की ओर झुकाव उसकी अस्तित्व पर खतरा है। इस कारण इस्राइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर साइबर हमलों (जैसे स्टक्सनेट) और वैज्ञानिकों की हत्या जैसे गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम दिया।

वैचारिक व धार्मिक मतभेद– ईरान और इस्राइल के बीच वैचारिक टकराव मुख्यतः धर्म, क्षेत्रीय नेतृत्व और अस्तित्व की राजनीति से जुड़ा हुआ है।

ईरान का इस्लामी क्रांतिकारी दृष्टिकोण– ईरान अपने आप को एक इस्लामी क्रांति के वाहक के रूप में प्रस्तुत करता है, और शिया इस्लाम के वैश्विक प्रसार का लक्ष्य रखता है। इसके लिए वह इस्राइल को इस्लाम के शत्रु के रूप में दिखाता है। वह फिलिस्तीन को इस्लामी भूमि मानता है, जिस पर यहूदी राज्य को स्वीकार करना उसके वैचारिक सिद्धांतों के विरुद्ध है।

इस्राइल का यहूदी राष्ट्रवाद और अस्तित्व का भय– इस्राइल, एकमात्र यहूदी राष्ट्र, स्वयं को इस्लामी आतंकवाद और घेराबंदी के बीच घिरा हुआ मानता है। वह ईरान के इस्राइल को मिटा देने जैसे वक्तव्यों को अपने अस्तित्व के लिए सीधी चुनौती मानता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed (Refereed) International Journal
Volume 04, Issue 06, June 2025

सुन्नी–शिया विभाजन और रणनीतिक स्थिति– हालाँकि इस्राइल यहूदी राष्ट्र है और ईरान शिया बहुल इस्लामी गणराज्य, लेकिन क्षेत्रीय नेतृत्व के लिए दोनों की टकराहट ने सुन्नी देशों को भी प्रभावित किया है। ईरान स्वयं को मुस्लिमों का रक्षक मानता है, जबकि इस्राइल पश्चिमी ताकतों के सहयोग से रणनीतिक बढ़त बनाए रखना चाहता है।

सामरिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ– ईरान और इस्राइल के बीच तनाव केवल वैचारिक या धार्मिक नहीं, बल्कि सामरिक स्तर पर भी गंभीर है। दोनों देशों की सुरक्षा नीतियाँ एक–दूसरे के विरुद्ध केंद्रित हैं।

ईरानी रक्षा नीति– ईरान की रक्षा नीति में मुख्य उद्देश्य इस्राइल को क्षेत्रीय शक्ति बनने से रोकना है। इसके लिए ईरान Axis of Resistance (प्रतिरोध की धुरी) की अवधारणा को बढ़ावा देता है, जिसमें सीरिया, लेबनान की हिज़्बुल्लाह और इराकी मिलिशियाएं शामिल हैं। ईरान ने इन संगठनों को हथियार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देकर एक प्रकार का Proxy Network स्थापित किया है।

इस्राइली सामरिक प्रतिक्रिया– इस्राइल की नीति Preemptive Strike Doctrine पर आधारित है। इस्राइल ने बार–बार संकेत दिया है कि वह ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल संयंत्रों पर हमले करने के लिए तैयार है। साथ ही, वह सीरिया में ईरानी सैन्य ठिकानों पर वायु हमले कर चुका है।

साइबर युद्ध और खुफिया गतिविधियाँ– दोनों देशों ने साइबर युद्ध में सक्रियता दिखाई है। 2010 में स्टक्सनेट वायरस द्वारा ईरान के नटांज़ परमाणु संयंत्र को क्षति पहुँचाई गई थी। ईरान ने भी तेल अवसंरचना और इस्राइली वेबसाइटों पर जवाबी साइबर हमले किए हैं।

ईरान का परमाणु कार्यक्रम और इस्राइली दृष्टिकोण

ईरान का दृष्टिकोण– ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए है। वह 1968 के परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षरकर्ता है, लेकिन कई बार उसने अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण एजेंसियों से असहयोग किया है, जिससे उसके इरादों पर संदेह बढ़ता है।

इस्राइली आपत्तियाँ– इस्राइल मानता है कि ईरान यदि परमाणु शक्ति बन गया, तो न केवल इस्राइल की सुरक्षा खतरे में होगी, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में परमाणु दौड़ शुरू हो सकती है। इस्राइल ईरान को Existential Threat (अस्तित्व का खतरा) मानता है। वह 2015 के ईरान परमाणु समझौते का विरोधी रहा और अमेरिका को उससे बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया।

JCPOA और क्षेत्रीय तनाव– JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) के अंतर्गत ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को सीमित किया था। लेकिन अमेरिका के बाहर निकलने (2018) और नए प्रतिबंधों के बाद, ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियाँ फिर से तेज कर दी हैं। इस्राइल ने कई बार इस कार्यक्रम पर सैन्य हमले की संभावना जताई है।

सीरिया, लेबनान और हिज़्बुल्लाह की भूमिका–

सीरिया में ईरानी प्रभाव– सीरिया में ईरान की उपस्थिति ने इस्राइल की चिंता बढ़ा दी है। ईरान ने बशर अल–असद सरकार को समर्थन देकर क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाया। इस्राइल ने सीरिया में ईरानी हथियार ठिकानों पर दर्जनों बार हवाई हमले किए हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed (Refereed) International Journal
Volume 04, Issue 06, June 2025

हिज़्बुल्लाह– ईरान का मोहरा– लेबनान में सक्रिय शिया संगठन हिज़्बुल्लाह ईरान का प्रमुख सहयोगी है। 2006 में इस्राइल–हिज़्बुल्लाह युद्ध ने दिखा दिया कि यह संगठन इस्राइल के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। हिज़्बुल्लाह के पास आज हजारों रॉकेट हैं, जो उत्तरी इस्राइल को निशाना बना सकते हैं।

Northern Front की रणनीति– इस्राइल की "Northern Front" नीति हिज़्बुल्लाह और ईरानी सेनाओं की सीरिया में बढ़ती उपस्थिति को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। इस्राइल नहीं चाहता कि उसके उत्तरी सीमांत पर ईरान–प्रेरित सेनाएं जमावड़ा बनाएं।

हमास और फिलिस्तीन संदर्भ में ईरान–इस्राइल की नीतियाँ

ईरान का समर्थन– ईरान हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे सुन्नी संगठनों का समर्थन करता है, हालाँकि वैचारिक मतभेद हैं। इसका उद्देश्य है इस्राइल को फिलिस्तीनी मोर्चे पर व्यस्त रखना। ईरान इन्हें वित्तीय सहायता और रॉकेट तकनीक प्रदान करता है।

इस्राइली नीति– इस्राइल हमास को आतंकवादी संगठन मानता है और गाज़ा पट्टी पर सैन्य कार्रवाई करता रहा है। इस्राइल के अनुसार, हमास का समर्थन कर ईरान फिलिस्तीनी मुद्दे को हथियार की तरह प्रयोग करता है।

गाज़ा संघर्ष और क्षेत्रीय प्रभाव– गाज़ा में समय–समय पर हुए संघर्षों ने मध्य पूर्व की राजनीति को झकझोरा है। 2021 और 2023 के संघर्षों में इस्राइल ने ईरान को परोक्ष रूप से दोषी ठहराया।

अमेरिका और पश्चिमी देशों की भूमिका

इस्राइल–अमेरिका रणनीतिक गठबंधन– अमेरिका और इस्राइल के बीच घनिष्ठ सामरिक, रक्षा और खुफिया सहयोग रहा है। अमेरिका, इस्राइल को व्यापक सैन्य सहायता प्रदान करता है और उसे स्ट्रैटेजिक एसेट मानता है। ईरान के विरुद्ध अमेरिकी प्रतिबंधों और सुरक्षा नीति में इस्राइल की भूमिका निर्णायक रही है।

ईरान–अमेरिका संबंधों का तनाव– 1979 के तेहरान दूतावास संकट के बाद से ईरान–अमेरिका संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम, आतंकवाद के समर्थन और मानवाधिकार हनन को लेकर कई बार प्रतिबंध लगाए हैं।

JCPOA (2015) और ट्रंप प्रशासन– ओबामा प्रशासन के समय हुआ JCPOA ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने का प्रयास था, लेकिन 2018 में ट्रंप प्रशासन ने इसे "Worst Deal" कहकर खत्म कर दिया और Maximum Pressure नीति अपनाई। इससे ईरान और अमेरिका के बीच टकराव फिर से तीव्र हो गया।

यूरोपीय संघ और कूटनीति– यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, JCPOA को बनाए रखने के पक्षधर रहे हैं और मध्यस्थता के प्रयास करते रहे हैं। लेकिन अमेरिका की भूमिका और ईरान का रुख, इस प्रक्रिया को बार–बार असफल बनाता रहा है।

रूस, चीन और वैश्विक दक्षिण का रुख

1. रूस और ईरान की रणनीतिक साझेदारी– सीरिया संकट के दौरान रूस और ईरान का सहयोग गहरा हुआ है। दोनों ने बशर अल–असद को समर्थन दिया और पश्चिमी प्रभाव को चुनौती दी। रूस ने कई बार संयुक्त राष्ट्र में इस्राइल विरोधी प्रस्तावों पर वीटो किया है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed (Refereed) International Journal
Volume 04, Issue 06, June 2025

2. चीन की ऊर्जा और आर्थिक प्राथमिकता– चीन ईरान के तेल और गैस का बड़ा खरीदार है और "Belt and Road Initiative" के माध्यम से ईरान में निवेश कर रहा है। 2021 में दोनों देशों के बीच 25 वर्षीय सामरिक साझेदारी समझौता हुआ। चीन ईरान को पश्चिमी प्रभाव से बाहर लाने की रणनीति अपना रहा है।

3. वैश्विक दक्षिण की संतुलित नीति– भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश ईरान–इस्राइल संघर्ष में सतर्क रहते हैं। भारत जैसे देश दोनों देशों से ऊर्जा व रक्षा साझेदारी बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी नीति संतुलन पर आधारित होती है।

अरब देशों का दृष्टिकोण और अब्राहम समझौते

1. पारंपरिक विरोध और नया समीकरण– ऐतिहासिक रूप से अरब राष्ट्र इस्राइल के विरोधी रहे हैं, लेकिन ईरान के बढ़ते प्रभाव ने इस समीकरण को बदला है। अब्राहम समझौते (2020) के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देशों ने इस्राइल को मान्यता दी है।

2. ईरान का विरोध, सुन्नी बनाम शिया तनाव– सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देश शिया ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता का स्रोत मानते हैं। इसलिए अब्राहम समझौते का एक उद्देश्य ईरान को रोकना भी रहा है।

3. सऊदी–इस्राइल संभावित समझौता– हाल ही में ऐसी चर्चाएँ रही हैं कि सऊदी अरब भी इस्राइल से संबंध सामान्य कर सकता है। हालाँकि फिलहाल फिलिस्तीन मुद्दा एक अवरोध बना हुआ है।

तेल, गैस और ऊर्जा भू–राजनीति

1. ईरान का ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण– ईरान दुनिया के चौथे सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार और दूसरे सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार वाला देश है। वह होरमुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से वैश्विक तेल व्यापार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

2. इस्राइल की ऊर्जा खोज और रणनीति– 2000 के दशक के बाद इस्राइल ने भूमध्यसागर में विशाल गैस भंडार खोजे हैं (Leviathan o Tamar)। इनसे इस्राइल ने ऊर्जा निर्यातक के रूप में खुद को स्थापित करना शुरू किया है।

3. ऊर्जा आपूर्ति पर संघर्ष का प्रभाव– यदि ईरान–इस्राइल युद्ध होता है, तो तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति संकट में आ सकती है। इससे न केवल ऊर्जा बाजार अस्थिर होंगे, बल्कि वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा भी बढ़ेगा।

साइबर युद्ध और गुप्त अभियान

1. साइबर युद्ध का नया मोर्चा– 21वीं सदी के युद्ध अब पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर डिजिटल दुनिया में भी लड़े जा रहे हैं। ईरान और इस्राइल के बीच साइबर हमले और प्रतिघात इस संघर्ष के मुख्य घटक बन चुके हैं।

स्टक्सनेट वायरस (2010)– अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान के नटांज़ यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को निशाना बनाकर लॉन्च किया गया यह वायरस साइबर युद्ध का पहला बड़ा उदाहरण था।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed (Refereed) International Journal
Volume 04, Issue 06, June 2025

ईरान की प्रतिक्रिया– ईरान ने इस्राइल की जल आपूर्ति, ऊर्जा संयंत्रों और बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले किए हैं।

2. मोसाद बनाम रिवोल्यूशनरी गार्ड्स– इस्राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की आईआरजीसी दोनों सक्रिय रूप से एक–दूसरे के वैज्ञानिकों, कमांडरों और ठिकानों को निशाना बनाते रहे हैं।

परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या– ईरान के कई वरिष्ठ वैज्ञानिक जैसे मोहसिन फखरीज़ादे की हत्या में इस्राइल पर आरोप लगे।

ईरान की प्रतिक्रियाएं– ईरान ने सीरिया, इराक और लेबनान में मोसाद एजेंट्स को लक्षित करने की कोशिश की।

कूटनीतिक प्रयास और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

1. संयुक्त राष्ट्र का सीमित हस्तक्षेप– संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम, हथियार आपूर्ति और आतंकवाद संबंधी गतिविधियों पर कई प्रस्ताव पारित किए हैं। हालांकि, रूस और चीन के वीटो की वजह से इस्राइल विरोधी कार्रवाइयाँ अक्सर अटक जाती हैं।

2. IAEA की भूमिका– अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ईरान के परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण करती है। उसकी रिपोर्टों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ईरान की नीयत और पारदर्शिता का संकेत मिलता है।

3. कूटनीतिक प्रयासों की असफलता– अब तक ईरान–इस्राइल टकराव को लेकर कोई ठोस वैश्विक शांति संधि नहीं हो सकी है। क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों की भिन्न प्राथमिकताएं शांति प्रयासों को बाधित करती हैं।

ईरान–इस्राइल टकराव का वैश्विक प्रभाव

1. तेल और ऊर्जा बाजार पर प्रभाव– हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाला तेल व्यापार यदि बाधित होता है, तो कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।

2. अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों पर असर– ईरान–इस्राइल युद्ध की स्थिति में नाटो, अरब लीग, संयुक्त राष्ट्र और BRICS जैसे समूहों की एकता पर असर पड़ सकता है। अमेरिका और यूरोप इस्राइल का समर्थन करेंगे, जबकि रूस–चीन तटस्थता या ईरान की ओर झुक सकते हैं।

3. मानवाधिकार और शरणार्थी संकट– संभावित युद्ध से लाखों लोगों को विस्थापन और मानवीय संकट का सामना करना पड़ सकता है, जैसा सीरिया और इराक में देखा गया है।

संभावित युद्ध के परिदृश्य

1. सीमित युद्ध– यह परिदृश्य केवल हवाई हमलों, मिसाइल हमलों और साइबर ऑपरेशनों तक सीमित हो सकता है। यह इस्राइल और ईरान के बीच टकराव को नियंत्रित रख सकता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम गाज़ा, सीरिया और लेबनान तक फैल सकते हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed (Refereed) International Journal
Volume 04, Issue 06, June 2025

2. प्रत्यक्ष पारंपरिक युद्ध– यदि टकराव पूर्ण सैन्य युद्ध में बदलता है, तो यह पश्चिम एशिया को कई दशकों पीछे ले जा सकता है। इस्राइल के मिसाइल रक्षा तंत्र और ईरान की मिलिशियाओं के बीच युद्ध के साथ, अमेरिका और अन्य शक्तियाँ भी शामिल हो सकती हैं।

3. परमाणु युद्ध की संभावना– हालांकि यह अत्यंत दुर्लभ और विनाशकारी परिदृश्य है, लेकिन यदि ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है, तो इस्राइल द्वारा pre & emptive nuclear strike की आशंका जताई जाती है।

4. शांति के लिए बाधाएँ और अवसर– शांति की राह में सबसे बड़ी बाधा आपसी अविश्वास है। लेकिन ऊर्जा सहयोग, व्यापार, मध्यस्थता और क्षेत्रीय साझेदारियों के माध्यम से यह अविश्वास कम किया जा सकता है।

शांति की संभावनाएं और सिफारिशें

1. शांति की वर्तमान संभावनाएं– हालांकि ईरान और इस्राइल के बीच गहरी वैचारिक खाई है, परंतु अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और क्षेत्रीय थकान ऐसे तत्व हैं जो स्थायी शांति की दिशा में संभावनाएं निर्मित कर सकते हैं।

आर्थिक थकावट– ईरान की आर्थिक स्थिति, प्रतिबंधों और सामाजिक असंतोष से प्रभावित है। इस्राइल भी निरंतर युद्ध की स्थिति में सुरक्षा और आर्थिक दबाव झेलता है।

क्षेत्रीय कूटनीति– सऊदी अरब–ईरान समझौता (2023) और अब्राहम समझौते जैसी पहलें यह दर्शाती हैं कि मध्य पूर्व में शांति की आकांक्षा बढ़ रही है।

2. सिफारिशें

1. संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ को नए प्रारूप के तहत शांति वार्ता पुनः प्रारंभ करनी चाहिए।
2. IAEA को अधिक स्वायत्त और पारदर्शी भूमिका सौंपी जानी चाहिए।
3. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर साइबर युद्ध और गुप्त अभियानों के विरुद्ध स्पष्ट नियम बनाए जाएं।
4. बुद्धिजीवियों, धार्मिक नेताओं, और पूर्व राजनयिकों के स्तर पर संवाद को बढ़ावा देना।
5. क्षेत्रीय ऊर्जा पाइपलाइन और वितरण के लिए ईरान और इस्राइल के बीच मध्यस्थ साझेदारी निर्मित की जा सकती है।
6. लेबनान, सीरिया और गाज़ा के शरणार्थी संकट पर दोनों पक्षों को मानवीय आधार पर काम करना चाहिए।
7. युवाओं में सह–अस्तित्व और बहुलतावाद के विचारों को प्रोत्साहित करने हेतु सांस्कृतिक परियोजनाएं चलाई जानी चाहिए।
8. उकसाने वाले प्रचार की बजाय संवाद–संवर्धनकारी सामग्री का प्रसार हो।
9. ईरान और इस्राइल दोनों में ऐसे संगठन सक्रिय हैं जो शांति के पक्षधर हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय सहयोग मिले।
10. अरब लीग, OIC, EU और UN की सम्मिलित साझेदारी से एक स्वतंत्र क्षेत्रीय वार्ता मंच की स्थापना।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A Monthly, Open Access, Peer Reviewed (Refereed) International Journal
Volume 04, Issue 06, June 2025

निष्कर्ष– ईरान और इस्राइल के बीच टकराव आधुनिक विश्व की जटिल भू–राजनीतिक संरचना का एक प्रतिनिधि उदाहरण है, जिसमें इतिहास, धर्म, कूटनीति, ऊर्जा, तकनीक और सैन्य रणनीति आपस में उलझे हुए हैं। यह टकराव केवल दो देशों के बीच नहीं, बल्कि एक पूरे क्षेत्र के भविष्य को तय करता है। यदि यह संघर्ष बढ़ता है, तो यह न केवल मध्य पूर्व को बल्कि पूरी दुनिया को गहरे संकट में डाल सकता है। किंतु यदि दोनों पक्षों सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय विवेकपूर्ण रणनीति, संवाद और समन्वय की दिशा में अग्रसर हो, तो शांति और सह–अस्तित्व के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। इस शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि युद्ध कोई समाधान नहीं, अपितु कूटनीति, समझदारी और साझा हित ही स्थायी समाधान की कुंजी हैं।

सन्दर्भ सूची–

1- Byman, Daniel. *Iran and the Bomb: The Threat and the Challenge.* Brookings Institution Press, 2012. ISBN: 9780815721985
2- Takeyh, Ray. *Guardians of the Revolution: Iran and the World in the Age of the Ayatollahs.* Oxford University Press, 2009. ISBN: 9780195395912
3- Karmon, Ely. *Iran and its Proxy Hezbollah: Strategic Challenges for Israel and the Region.* Routledge, 2020. ISBN: 9780367322461
4- International Atomic Energy Agency (IAEA) Reports (2015–2024)
5- United Nations Security Council Resolutions on Iran and Israel (2006–2023)
6- The Abraham Accords Documents (2020) – U.S. Department of State
7- The JCPOA Agreement – Official Texts and Updates (2015, 2018, 2021)
8- Hiltermann, Joost. "The Middle East's New Geopolitics." *International Crisis Group*, 2023.
9- Katz, Yaakov. *Shadow Strike: Inside Israel's Secret Mission to Eliminate Syrian Nuclear Power.* St. Martin's Press, 2019. ISBN: 9781250199826
10- Global Energy Outlook Reports – IEA (2020–2024)
11- Carnegie Middle East Center – Iran-Israel Relations Archives
12- Haaretz and Al Jazeera News Archives (2010–2024)
13- "Cyber Conflict Between Iran and Israel" – *Council on Foreign Relations*, 2022.
14- "The Role of China in the Middle East" – *Brookings Institution*, 2023.
15- "Iran-Israel Shadow War in Syria" – *The Guardian*, 2021.
16- Jagran.com 25 June 2025
17- Amarujala.com 26 June 2025